

दिनांक	आज्ञा पत्र	
1-7-24	<p>पत्रावली पेश / कठिन उभय पक्ष उप तहत का रिक्त जाल / कार्यालय 10 दिनांक 22-7-24 को पेश है।</p> <p>भू-प्रवन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील-अधिकारी सीकर</p>	
२२. 7. 24	<p>पत्रावली पेश / ७६६ उभयपक्ष सुनी गडी पत्रावली वादों का फैसला दिनांक 5/8/24 को पेश है।</p> <p>भू-प्रवन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर</p>	
5/8/24	<p>पत्रावली पेश । अपील अपीलान्त..... की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फंसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तत्पश्चात् तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p>भू-प्रवन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर</p>	

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 30/2021

1 किशोर कुमार पुत्र स्व. श्री सांवलराम

2 पुरुषोत्तम पुत्र स्व. श्री सांवलराम

3 रमेश पुत्र स्व. श्री सांवलराम

समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम पचार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।



अपीलांत

बनाम

1 मालीराम पुत्र श्री भूराराम जाति कुमावत निवासी ग्राम पचार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

2 उप पंजीयक दांतारामगढ़ जिला सीकर।

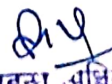
3 पटवारी, पटवार हल्का पंचार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

4 राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारक तहसीलदार महोदय, तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेंट

अपील विरुद्ध आज्ञा न्यायालय उपखण्ड
अधिकारी दांतारामगढ़ जिला सीकर आदेश
दिनांकित 01.03.2021 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत
धारा 212 आर.टी.एक्ट बउनवानी मालीराम
बनाम रुकमणी आदि प्रार्थना पत्र संख्या

94/2012


भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री निर्मल कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलांत
2. श्री मुकेश कुमार कुमावत, अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट

-निर्णय-

दिनांक:- 5.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतरामगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 94/2012 में पारित निर्णय दिनांक 01.03.2021 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी/रेस्पोजेन्ट नम्बर 1 एक आवेदन धारा 212 बाबत भूमि खसरा नम्बर 1163, 1199, 1200, 1202 वाके ग्राम पंचार का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांत ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के अन्तर्गत रेस्पोजेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा के अन्तर्गत यह कथन वर्णित किया गया कि वादग्रस्त खसरा की भूमियां जिसका मूल रूप से खसरा नम्बर 387 रकबा 62 बीघा 05 बिस्वा से ही नये खसरा नम्बर 1163, 1199, 1200 व 1202 कायम किये गये है किन्तु रेस्पोजेन्ट संख्या 01 के द्वारा विचारण न्यायालय में प्रस्तुत वाद के अन्तर्गत केवल मात्र 1/4 के सहखातेदार काशतकार अपीलान्त को ही पक्षकार

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन सहायक अपील अधिकारी
सीकर

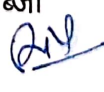


मुकदमा संयोजित कर बाद एवं आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया तथा भूमियों पर कदीम से अपने पिता व दादा के समय से कब्जा काशत होने का कथन किया गया। जिसके सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं था। इस बाबत अपीलान्ट के द्वारा अपने जवाब में समुचित आपत्ति करने के बावजूद कि उक्त भूमियों के अन्तर्गत खसरा नम्बर 387 के सभी खातेदार, काशतकार प्रकरण में आवश्यक पक्षकार की संज्ञा में आते हैं, कि आपत्ति को अमान्य करते हुये रेस्पोजेन्ट संख्या 01/प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों को तवज्जो देते हुये अविधि रूप से उसके आवेदन 212 आर.टी.एक्ट. को स्वीकार कर अपीलान्ट को गलत रूप से भूमियों के उपयोग-उपभोग में बाधा पहुँचाते हुये उनको प्रतिबन्धित किया गया है रिकार्ड व मौका की यथास्थिति का आदेश दिया गया है। विचारण न्यायालय के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन व जवाब आवेदन के पश्चात न्यायालय को प्रथम दृष्टया प्रकरण की विवेचना करते समय यह मुख्य रूप से देखना होता है कि न्यायालय के समक्ष कौन व्यक्ति सदभाविक रूप से उपस्थित हुआ है तथा उसके द्वारा ऐसा कोई प्रश्न खड़ा किया गया है, जिसका समुचित निर्णय साक्ष्य के उपरान्त किया जाना आवश्यक है, किन्तु विचारण न्यायालय के द्वारा प्रथम दृष्टया मामले का विश्लेषण करने में गलत रूप से यह निष्कर्ष दिया कि रेस्पोजेन्ट संख्या 01/प्रार्थी के पूर्वज उपकृषक रहे हैं, किन्तु किसी भी प्रकार से दस्तावेज व गिरदावरियों का उल्लेख नहीं किया गया कि कौनसे साल-संवत् की गिरदावरियों में ऐसा वर्णन किया गया है तथा इस निष्कर्ष पर पहुचने का कोई विश्लेषणात्मक वर्णन नहीं किया गया कि मूल खसरा नम्बर 387 रकबा 62 बीघा 05 बिस्वा की भूमि जब एक ही खसरे के अन्तर्गत थी तो फिर अकेले अपीलान्ट के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करने तथा उन्हीं के हिस्सा विशेष की भूमि में रेस्पोजेन्ट संख्या 01/प्रार्थी का कब्जा काशत का आधार किस रूप में मान्य किया गया है। ऐसा कोई निष्कर्ष वर्णन नहीं करके अस्पष्ट रूप से न्यायालय के द्वारा प्रथम दृष्टया केस का निर्णय करते समय न्यायिक विवके का उपयोग नहीं किया गया तथा केवल मात्र कयास के आधार पर रेस्पोजेन्ट संख्या 01 के

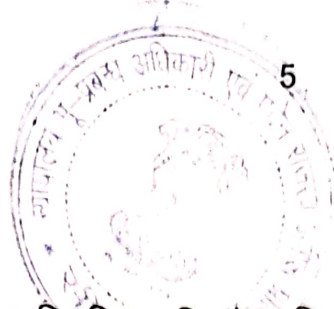
मुजबब्त अधिकारी एवं
पट्टेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर



अभिवचनों को गलत रूप से मनमर्जी मुताबिक मान्य करते हुये निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय के अन्तर्गत अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब आवेदन के अन्तर्गत यह स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया था कि मूल खसरा नम्बर 387 के अन्तर्गत 1/2 हिस्से के खातेदार किशनलाल पुत्र श्री चतरुभुज तथा 1/2 हिस्से के अन्तर्गत बालचन्द, सांवलराम पुत्रगण आनन्दीलाल है जिस आधार पर अपीलान्ट जो सांवलराम के वंशज है, जिनका भूमियों में 1/4 हिस्सा है, जिनका सम्वत 2011 से 2027 तक की खतौनी बंदोबस्त के अन्तर्गत समुचित नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा सांवलराम की मृत्यु के पश्चात अपीलान्ट व उनकी माता का नाम रिकार्ड में दर्ज किया गया। उक्त समुचित कार्यवाही में कभी भी रेस्पोंडेंट संख्या 01 द्वारा अथवा उनके पिता व दादा के द्वारा अपने जीवनकाल में आपत्ति नहीं की गयी तो किस प्रकार रिकॉर्डेड खातेदार के विरुद्ध अजनबी व्यक्ति के द्वारा खातेदारी उद्घोषणा का वाद का आवेदन कानूनी रूप से चलने योग्य है तथा वह किस प्रकार से रिकॉर्डेड खातेदार को उसी भूमियों के उपयोग-उपभोग से वंचित करने का कुप्रयास रखता है। इस स्थिति के होते हुये भी विचारण न्यायालय के द्वारा प्रथम दृष्टया मामले का विवेचन गलत रूप से करके रिकार्डेड खातेदार को उसकी भूमियों के उपयोग-उपभोग में बाधा डालने का कार्य किया है जो निर्णय किसी भी अनुरूप स्थित रहने योग्य नहीं वरन खारिज किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने तर्क दिया कि प्रार्थीगण के पूर्वज उपकृषक रहे है तथा पूर्व की गिरदावरियों में प्रार्थी के पूर्वज स्व भैरूराम का नाम अंकन है। प्रार्थी का विवादित भूमियों में हित निहित है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है क्योंकि प्रार्थी के पूर्वज उपकृषक रहे है तथा पूर्व की गिरदावरियों से स्पष्ट है कि प्रार्थी का विवादित भूमियों में कब्जा काशत रहा है। विवादित भूमियों का मूलवाद के निस्तारण तक यदि बेचान, 

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
रीकॉर्ड



हस्तांतरण तथा मौका स्थिति आदि में परिवर्तन होता है तो अपूरणीय क्षति प्रार्थी को होगी। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के हितो का निर्धारण मूलवाद में तय होना है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य का बिन्दुवार विवेचन कर प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु तय कर विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के पूर्वज उपकृषक रहे है तथा पूर्व की गिरदावरियों में प्रार्थी के पूर्वज स्व भैरुराम का नाम अंकन है। प्रार्थी का विवादित भूमियों में हित निहित है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है क्योंकि प्रार्थी के पूर्वज उपकृषक रहे है तथा पूर्व की गिरदावरियों से स्पष्ट है कि प्रार्थी का विवादित भूमियों में कब्जा काशत रहा है। विवादित भूमियों का मूलवाद के निस्तारण तक यदि बेचान, हस्तांतरण तथा मौका स्थिति आदि में परिवर्तन होता है तो अपूरणीय क्षति प्रार्थी को होगी। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के हितो का निर्धारण मूलवाद में तय होना है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य का बिन्दुवार विवेचन कर प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु तय कर विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीक

निर्णय आज दिनांक 5.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।



(बलदेवाराधु धोषक)
मुख्य अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अधिकारी,
सीकर